

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिपा

भारतीय बस्ती

बस्ती 21 सितम्बर 2024 शनिवार

सम्पादकीय

बच्चों महिलाओं पर बढ़ते अपराध

हाल ही के दिनों में बच्चों व महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर देशव्यापी चिंता कई मंचों से उजागर हुई है। इन अपराधों के प्रति पुलिस व एजेंसियों की संवेदनहीनता पर अदालतें गाहे-बगाहे सख्त टिप्पणियाँ कर चुकी हैं। कुछ समय पहले जिला अदालतों के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भी महिलाओं व बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर गंभीर चिंता जतायी थी। साथ ही त्वरित न्याय से समाधान की बात कही थी। देश के राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो यानी एनसीआरबी के वे आंकड़े विचलित करते हैं, जिसमें कहा गया था कि साल 2022 में भारत में हर घंटे में औसतन 18 बच्चे अपराधों के शिकार बने। वहीं पिछले एक दशक में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 75 फीसदी वृद्धि की बात एनसीआरबी ने स्वीकारी है। इसको के खिलाफ होने वाले अपराधों की गंभीरता को बच्चों से समाजा जा सकता है कि वर्ष 2023 में बीते वर्ष की तुलना में जहां अपराधों में कमी दर्ज की गई, वहीं दूसरी ओर बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों में नौ फीसदी की वृद्धि एनसीआरबी के आंकड़ों में दर्ज की गई। यह हमारे नीति-निर्णयताओं के लिये गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए कि देश में बच्चों के खिलाफ अपराधों में क्यों लगातार वृद्धि हो रही है। विडंबना यह है कि एनसीआरबी केवल उन्हीं अपराध के आंकड़ों का उल्लेख करता है, जो थानों में दर्ज होते हैं। दरअसल, बच्चों के खिलाफ बढ़ी संख्या में होने वाले अपराध अक्सर दर्ज ही नहीं होते। कानूनी जानकारी न होने और थानों व कचहरियों के चक्कर काटने से बचने के लिये अभिभावक कई मामलों में रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करवाते। कुछ मामलों को पुलिस संकट करने से बचती है। ऐसे में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की वास्तविक स्थिति का आकलन करना सहज नहीं होगा।

बहरहाल, व बढ़ते अपराध हमारे समाज में गहरी होती संवेदनहीनता और समाज में नैतिक मूल्यों के पराभव की ओर भी इशारा करती है।

दरअसल, बच्चों के खिलाफ अपराध केवल हमारे सामाजिक व्यवस्था में ही नहीं बड़े, बल्कि इसका दायरा वरुञ्जल दुनिया में भी तेजी से बढ़ा है। बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों में खासरी तेजी आई है। चौकाने वाली बात यह है कि वर्ष 2022 में बच्चों के विरुद्ध पहले साल के मुकाबले बलीसदी अधिक साइबर अपराध दर्ज हुए। जो निरंतर गंभीर होती स्थिति को दर्शाते हैं। हाल के दिनों में स्कूल-कॉलेजों में ऑनलाइन प्रदाई का दायरा बढ़ने और मोबाइल की सहज उपलब्धता से बच्चों की इस क्षेत्र में सक्रियता बढ़ी है। सरले इंटरनेट व मोबाइल फोन से बच्चों के लिये सोशल मीडिया व गेमिंग की दुनिया में पहुंच आसान बनायी है। लेकिन बच्चे इंटरनेट की आपराधिक दुनिया से अनजान हैं। उन्हें इन खतरों से बचाव को प्रशिक्षण न तो स्कूल में दिया जाता है और न ही पुरानी पीढ़ी के अभिभावक दे पाए। जिसके चलते ही वे साइबर अपराधियों का आसान शिकार बनते हैं। दरअसल, कोरोना महामारी तो चली गई, लेकिन इस संकट के चलते उपजी स्थितियों ने बच्चों के ऑनलाइन रहने का टाइम बढ़ा दिया है। अभिभावक यदि बच्चों को अधिक मोबाइल के इस्तेमाल पर टोकते हैं तो वे स्कूल के काम का लक्ष्य देकर गेमिंग व सोशल मीडिया की गतिविधियों में लगे रहते हैं। यह समय का बड़ा संकट है कि बच्चे न तो अभिभावकों से संस्कार पा रहे हैं और न ही शिक्षकों से। उन्हें मोबाइल पर संस्कार व अनाम व अज्ञात कंपनियां दे रही हैं, जिन्हें लिये बच्चे महज उम्पत्ताओं और पैसा कमाने का जरिया हैं। आज इंटरनेट के खुले और छिपे स्वरूप पर अपराधों की एक ऐसी समारंभ दुनिया संचालित है, जिन्हें दुनिया की ताकतवर सरकारें भी नियंत्रित नहीं कर पा रही हैं। दरअसल, अधिकांश बच्चे इस चुनौती के मुकाबले के लिये डिजिटली साक्षर नहीं हो पाए हैं। इसके लिये साइबर कानून को अडिग सशक्त व प्रभावी बनाने की जरूरत है। ताकि बच्चों के खिलाफ अपराध, धोखाधड़ी व साइबर बुलिंग करने वाले अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सके। निश्चित रूप से आज देश के सताधीशों को साइबर अपराधों से बच्चों व महिलाओं को सुरक्षित बनाने के लिये कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा।

चुनावी घोषणा पत्र, वायदों पर कितना भरोसा



—अजय कुमार—

भारतीय राजनीति में मुफ्त योजनाओं का चलन पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है, और यह एक ऐसी रणनीति बन गई है जिसे राजनीतिक दल अपने चुनावी अभियानों में बड़ी चतुराई से इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुफ्त पानी और बिजली देने का मॉडल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुफ्त राशन देने का कार्यक्रम, ये सभी नीतियां राजनीतिक सफलता की कुंजी बन चुकी हैं। परिचय बंगाल की मनात बनर्जी से लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तक, सभी ने इन योजनाओं का उपयोग करके अपनी सत्ता को मजबूत किया है। अब हरियाणा में कांग्रेस ने इसी परंपरा को अपनाते हुए अपने चुनावी अभियान में एक नया मॉडल दिया है, जिससे वह पिछले दस वर्षों से सत्ता से बाहर रहने की स्थिति को बदलने का प्रयास कर रही है।



कांग्रेस ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में कई आकर्षक वादे पेश किए हैं। इनमें से प्रमुख वादा 300 युनिट मुफ्त बिजली देने का है, जो सीधे अरविंद केजरीवाल के मॉडल से प्रेरित है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस ने समझ लिया है कि लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं ही उनकी राजनीतिक जीत की कुंजी हो सकती हैं। कांग्रेस के नेता इस बात पर अत्यंत संतुष्ट हैं और उन्होंने इन योजनाओं को लुभावना बनाने की हर संभव कोशिश की है।

यह वादा दुष्टियों की ध्यान देने योग्य हैं। पार्टी ने 18 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक महिला को प्रतिमात्र 2000 रुपये देने का वादा किया है। यह योजना मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से प्रेरित है, जिसने उस राज्य में चुनावी परिणामों को पलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांग्रेस का यह वादा महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देकर उन्हें अपने घर में रहने की एक रणनीति है। इसके अतिरिक्त, बुजुर्ग दिव्यांगों और विधवाओं को भी छह हजार रुपये की प्रत्येक महीने का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुखसा योजना है।

लिया कांग्रेस ने एमएसपी (रयूनत सफरथन मूवा) को कानूनी गारंटी देने का वादा किया है। यह घोषणा किसानों के हित में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और इससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने ग्रामीण समुदाय की वित्ताओं को समझा है। भारतीय राजनीति में किसानों का एक अहम स्थान है, और उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना हमेशा से राजनीतिक दलों के लिए फायदेमंद रहा है। इसके अलावा, कांग्रेस ने किसानों को सुरत मुआवजे का आश्वासन देकर उनकी समस्याओं को तेजी से हल करने का भी वादा किया है।

किसानों को आकर्षित करने के लिए कांग्रेस का प्रति घोषणा पत्र

किसानों को मिले उनका हक



—अशोक गुलाटी—

2024 में संसदीय चुनाव होने से पहले ही, नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी सचिवों को सरकार के अंतिम 100 दिनों में घोषित किए जाने वाले नीतिगत एजेंडे को तैयार करने के लिए नियुक्त किया था। उन्हें पूरा भरोसा था कि 5 साल में पार्टी भारी बहुमत के साथ वापस आ रही है। संसदीय चुनावों के वास्तविक परिणाम पार्टी के लिए निराशाजनक थे, क्योंकि यह 370 के अपने लक्ष्य से बहुत पीछे रह गई। फिर भी, पहले 100 दिनों का उल्लास बेतानी नहीं देता है। भाजपा अब गठबंधन सरकार चला रही है, इसलिए उसे अपने प्रमुख सहयोगियों, खासकर प. चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की मांगों को पूरा करना होगा ताकि सरकार बिना किसी परेशानी के अपना काम जारी रख सके। दिनेश व्या अलग किया है? जबकि विनिर्माण, खासकर हाई-टेक चिप निर्माण आदि पर समझौते हैं, अन्य क्षेत्रों में भी कई बदलाव हुए हैं। मैं इस कोलम में उन सभी को शामिल नहीं कर सकता, न ही मेरे पास उन क्षेत्रों में किए जा रहे कदमों की दरता का विश्लेषण और आकलन करने की विशेषज्ञता है। मैं खुद को कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र तक सीमित रखूंगा जो आम जनता के कल्याण को सबसे अधिक प्रभावित करता है।

कृषि के मांचे पर मोदी सरकार (मौदी 3.0) की शुरूआत कृषि और किसान कल्याण के लिए नए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई, और उन्हें ग्रामीण विकास का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। फ्रय प्रदर्शन के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले और मजदूर पार्टी के नेता को बदलने वाले प्रदाई अनुभव वाले मंत्री को लाना, एक उच्च प्राथमिकता का संकेत है जिसे मंत्री 3.0 के तहत कृषि और ग्रामीण विकास मिले संकात है। पहला बांध फंडसा जो लिया गया, वह था पी. एफ. किसान योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए वितरित करने, जो 2019 में की गई प्रतिबद्धता थी, जिसके तहत अधिकांश योग्य कृषि परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। इसने स्पष्ट संकेत दिया कि पी.एफ.—किसान

पिछले 5 वर्षों में मुद्रास्फीति के लिए इसका नाममात्र मूल्य समायोजित किया जाएगा, और 6,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर कम से कम 8,000 रुपए प्रति परिवार कर दिया जाएगा, लेकिन यह उम्मीद झूठी साबित हुई। केंद्रीय बजट 2024-25 में भी, हमने जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने के लिए कृषि—आर.एफ.डी. आवंटन में बड़ी कृषि को उम्मीद की थी। लेकिन बजट आवंटन में भी बहुत अधिक वास्तविक वृद्धि नहीं हुई। यह हमेशा की तरह ही लगा रहा था। लेकिन प्रमुख घोषणाएं बाद में हुईं, जो कुछ हद तक आश्चर्यजनक थीं, जब कई सरकार ने कृषि के लिए 7 योजनाओं को मंजूरी दी, जिन्हें कृषि के डिजिटलीकरण (डिजीटाइजेशन) किसानों के पहचान पत्र, आदि) से लेकर जलवायु परिवर्तन की चुभुनी में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फलस वितरण, पोषण और लाभप्रदा के लिए बागवानी, स्थिरता और लाभप्रदा के लिए पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन, जलवायु लचीलेपन और स्वच्छ परिवहन के लिए प्राकृतिक संस्करण बनाने, कृषयमान संसाधनों के लिए कृषि शिक्षा और किसानों के लिए बेहतर पहुंच के लिए कृषि विज्ञान केंद्र शामिल हैं। इन योजनाओं को अगले 2-3 सालों में लागू करने के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये सभी कदम सही दिशा में उठाए गए हैं और अगर इन्हें सही तरीके से और जल्दी से लागू किया जाय तो वे बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कृषि के डिजिटलीकरण के उदाहरण से मैं इसे समझाता हूँ। किसानों की पहचान करना कदम है। मलिक-संसाधन और कारखानक के बीच अंतर करना अनाया कदम है। अभी भारत का आधिकारिक आंकड़ा लगभग 17 प्रतिशत कारखानक का है, जो सूक्ष्म संरक्षणों से पता चलने वाले आंकड़ों से काफी कम है। यह 25 से 30 प्रतिशत के बीच हो सकता है, अगर इससे ज्यादा नहीं।

भेड़िये के हमलावर होने का सच

—जयसिंह रावत—

इन दिनों भेड़िया बहराच में लोगों की रातों की नींद और दिन का चीन उड़ा रहा है। देखा जाए तो भेड़िये को शेर और बाघ जैसे मांसाहारी जानवरों की तरह अत्यंत खूबार माना जाता रहा है। विशेषकर भेड़िये को बहुत शमील और मनुष्य से बचकर रहने वाला मानते हैं। वास्तव में, बच्चों पर कुछ हमलों के अलावा किसी बयस्क पर हमले के कम ही दृष्टान्त मिलते हैं। भेड़िये के कथित खौफ और उसके प्रति इंसान की बदले की भावना के कारण प्रकृति का यह एक महत्वपूर्ण जीव अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है। इसकी आबादी भारत में 3 हजार से कम रह गई है। इसीलिए वन्यजीव अधिनियम में बाघ और शेरों के साथ इसे भी अति संरक्षित जीवों की सूची में रखा गया है। लेकिन संरक्षण तो रखा पूरू, उसे बचाने के भी कोई उपाय नजर नहीं आता।



उत्तर प्रदेश में 1996-97 के बाद पहली बार भेड़ियों का इतने बड़े पैमाने पर आतंक देखा जा रहा है। इंटर्नेशनल सेंटर फॉर वॉल्फ के अनुसार इसमें छपे एक शोध के तनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्ष 1996 में बच्चों पर भेड़ियों के हमले अपने चरम पर पहुंचे। उस समय भेड़ियों ने 76 बच्चों पर हमले किए थे, जिनमें से 50 बच्चों की मौत हो गई थी। उ.प्र. के अन्य हिस्सों में भी वर्ष 1997, 1998 और 1999 में बच्चों पर हमलों की घटनाएं दर्ज हुईं। दरअसल, यह मामला भी मानव-वन्यजीव संर्ष का है, जिसमें अकेले भेड़िये को गुनहवार नहीं माना सकते। अगर दशकों बाद भेड़िया जनता के मानव जीवन के लिए संकट बनकर बाहर निकला है, तो इस समस्या का समाधान भेड़ियों की नरल को समाप्त करने में नहीं, बल्कि इंसान और भेड़ियों के बीच संर्ष को समाप्त करना होना चाहिए ताकि दोनों ही जीवित रहें। धरती के हर जगह का होना जरूरी है और अगर धरती पर खूबारा मांसाहारी और शाकाहारीयों में संतुलन बिगड़ जाय, तो शाकाहारी जीव वन्यजीव जनत का विनाश कर डालेंगे। इसीलिए उन्मकी संख्या नियंत्रित करने के लिए प्रकृति में मांसाहारी का रूतन किया है। भारतीय भेड़िया दुनिया में जीवित भेड़ियों की सबसे प्राचीन वंशावली है और भारत में इसकी वंशावली 8 लाख साल पुरानी मानी जाती है।

उत्तर प्रदेश में 1996-97 के बाद पहली बार भेड़ियों का इतने बड़े पैमाने पर आतंक देखा जा रहा है। इंटर्नेशनल सेंटर फॉर वॉल्फ के अनुसार इसमें छपे एक शोध के तनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्ष 1996 में बच्चों पर भेड़ियों के हमले अपने चरम पर पहुंचे। उस समय भेड़ियों ने 76 बच्चों पर हमले किए थे, जिनमें से 50 बच्चों की मौत हो गई थी। उ.प्र. के अन्य हिस्सों में भी वर्ष 1997, 1998 और 1999 में बच्चों पर हमलों की घटनाएं दर्ज हुईं। दरअसल, यह मामला भी मानव-वन्यजीव संर्ष का है, जिसमें अकेले भेड़िये को गुनहवार नहीं माना सकते। अगर दशकों बाद भेड़िया जनता के मानव जीवन के लिए संकट बनकर बाहर निकला है, तो इस समस्या का समाधान भेड़ियों की नरल को समाप्त करने में नहीं, बल्कि इंसान और भेड़ियों के बीच संर्ष को समाप्त करना होना चाहिए ताकि दोनों ही जीवित रहें। धरती के हर जगह का होना जरूरी है और अगर धरती पर खूबारा मांसाहारी और शाकाहारीयों में संतुलन बिगड़ जाय, तो शाकाहारी जीव वन्यजीव जनत का विनाश कर डालेंगे। इसीलिए उन्मकी संख्या नियंत्रित करने के लिए प्रकृति में मांसाहारी का रूतन किया है। भारतीय भेड़िया दुनिया में जीवित भेड़ियों की सबसे प्राचीन वंशावली है और भारत में इसकी वंशावली 8 लाख साल पुरानी मानी जाती है।

उत्तर प्रदेश में 1996-97 के बाद पहली बार भेड़ियों का इतने बड़े पैमाने पर आतंक देखा जा रहा है। इंटर्नेशनल सेंटर फॉर वॉल्फ के अनुसार इसमें छपे एक शोध के तनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्ष 1996 में बच्चों पर भेड़ियों के हमले अपने चरम पर पहुंचे। उस समय भेड़ियों ने 76 बच्चों पर हमले किए थे, जिनमें से 50 बच्चों की मौत हो गई थी। उ.प्र. के अन्य हिस्सों में भी वर्ष 1997, 1998 और 1999 में बच्चों पर हमलों की घटनाएं दर्ज हुईं। दरअसल, यह मामला भी मानव-वन्यजीव संर्ष का है, जिसमें अकेले भेड़िये को गुनहवार नहीं माना सकते। अगर दशकों बाद भेड़िया जनता के मानव जीवन के लिए संकट बनकर बाहर निकला है, तो इस समस्या का समाधान भेड़ियों की नरल को समाप्त करने में नहीं, बल्कि इंसान और भेड़ियों के बीच संर्ष को समाप्त करना होना चाहिए ताकि दोनों ही जीवित रहें। धरती के हर जगह का होना जरूरी है और अगर धरती पर खूबारा मांसाहारी और शाकाहारीयों में संतुलन बिगड़ जाय, तो शाकाहारी जीव वन्यजीव जनत का विनाश कर डालेंगे। इसीलिए उन्मकी संख्या नियंत्रित करने के लिए प्रकृति में मांसाहारी का रूतन किया है। भारतीय भेड़िया दुनिया में जीवित भेड़ियों की सबसे प्राचीन वंशावली है और भारत में इसकी वंशावली 8 लाख साल पुरानी मानी जाती है।

